

एम० ए० गांधी एवं शांति अध्ययन

द्वितीय-सेमेस्टर

डॉ अम्बिकेश कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
मोतीहारी बिहार

4008 Understanding Conflict: Basic Theories

४००८ संघर्ष की समझ: आधारभूत सिद्धांत

सुरक्षा दृष्टिकोण के अलावा सशस्त्र संघर्षों को समझने और समझने के लिए कुछ और दृष्टिकोण हैं, सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य उनमें से एक है। इस परिप्रेक्ष्य का मूल तर्क है, क्योंकि 'समानता समान रूप से सभी तक नहीं पहुंचती है' इसलिए 'समानों के बीच असमानता है' और ऐसी सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ सशस्त्र संघर्षों का कारण बनती है, क्योंकि इस तरह असमानताएं वंचित वर्ग में निराशा पैदा होती है और लोग अपने उचित अधिकार को पाने के लिए हिंसक होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य का तर्क है कि विश्वास निर्माण उपायों के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में आबादी के दिलों और दिमागों को जीतकर सशस्त्र हिंसा की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं और कानून और शांति को बहाल किया जा सकता है।

सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य:

न्यायपूर्ण और समावेशी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के माध्यम से, दिल और दिमाग को जीतना, एक अवधारणा है जिसे युद्ध, उग्रवाद और अन्य संघर्षों के समाधान में अक्सर प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें एक पक्ष बेहतर बल के उपयोग से नहीं, बल्कि भावनात्मक या बौद्धिक अपील द्वारा प्रबल होने की कोशिश करता है। "दिल और दिमाग" शब्द का उपयोग सबसे पहले लुइस ह्यूबर्ट गोज़ाल्वे लियायुते (एक फ्रांसीसी सामान्य और औपनिवेशिक प्रशासक) ने 1895 में ब्लैक फ्लैग्स विद्रोह का मुकाबला करने के लिए गुलाम-आबादी को एक तरफ लाने की एक विधि का संदर्भ देने, की अपनी रणनीति के तहत किया था। अधिक प्रसिद्ध रूप से, यह शब्द-युग्म का मलय-आपातकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मलय लोगों के भरोसे को चिकित्सा और भोजन द्वारा मलेशियाई और स्वदेशी जनजातियों को सहायता कर, बनाए रखने के लिए और नृजातीय चीनी कम्युनिस्टों के साथ के प्रति झुकाव को कम करने के लिए किया गया था।

दिल और दिमाग को जीतने की रणनीति में लक्ष्यों को पूरा करने, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने से ज्यादा और भी बहुत कुछ शामिल है। यह परिप्रेक्ष्य रणनीति के तीन प्रमुख आयामों

पर ध्यान केंद्रित करता है: संसाधनों को अर्जित करने की और उनका उचित वितरण; स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के बीच सामुदायिक जीवन और बेहतर आपसी संबंधों को बनाए रखना; और भूमि और संसाधनों पर शक्ति और प्रभाव के अधिक से अधिक विस्तार को प्राप्त करना। ऐसे रणनीतिक लाभों को प्राप्त करना राज्य की क्षमताओं पर निर्भर करता है ताकि वे अपने बारे में दूसरों की धारणाओं को बदल सकें। राज्य, अगर यह एक नाजुक राज्य नहीं है तो को जनता के दिलों और दिमागों को जीतने में सक्षम होना चाहिए। विद्वानों, जैसे के.एस. सुब्रमण्यन (2005), नंदिनी सुंदर (2012), ब्रेडन जी किंग और एडवर्ड टी वॉकर (2014) और अन्य का तर्क है कि सशस्त्र संघर्ष के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श को फिर से परिभाषित करने की गंभीर आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के शोध और नीति (आरएंडपी) डिवीजन के एक अध्ययन रिपोर्ट (1969) में 'कॉज एंड नेचर ऑफ करंट एग्रेसिवन अनरेस्ट' शीर्षक से यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते ही भूमि वितरण के उचित उपाय नहीं किए गए और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नहीं लिया गया तो 'हरित क्रांति' 'लाल क्रांति' में बदल सकती है। भारत के माओवादी सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में, के.एस. सुब्रमण्यन (2005) लिखते हैं, ग्रामीण गरीबों के हितों पर आधारित नक्सली आंदोलन को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के विचार-विमर्श के अलावा शायद 'आंतरिक सुरक्षा' के मामले में उपयोगी नहीं माना जा सकता।

सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, कई शोधों से पता चलता है कि, एक सशस्त्र संघर्ष के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो नीति विश्लेषण के केंद्र में कभी नहीं रहे हैं। गरीबी, असमानता और समाज के अन्य पिछड़ेपन के मुद्दों को संबोधित किए बिना, एक सशस्त्र संघर्ष कैसे निपट सकता है। यह सच है कि सशस्त्र संघर्ष का जन्म प्रशासन और लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थानों की उदासीनता के कारण पैदा हुए शून्य में होता है; हालांकि, ये संस्थान संरचनात्मक अन्याय को खत्म करने और उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत से केस स्टडी:

मरि श्री श्रयतां यशः

फरवरी 2009 में, भारत की केंद्र सरकार ने एक नई राष्ट्रव्यापी पहल की घोषणा की, जिसे सभी प्रभावित राज्यों, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नक्सली समस्या से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित कार्यों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई जिसे 'एकीकृत कार्य योजना' (IAP) कहा जाता है। इस योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तृणमूल स्तर पर आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराना, साथ ही बेहतर नियंत्रण और माओवादी प्रभाव को कम करने के लिए विशेष पुलिस वित्त पोषण भी बढ़ाना शामिल था। अगस्त 2010 में, राष्ट्रीय IAP कार्यक्रम के लागू होने के पहले पूरे वर्ष के बाद, कर्नाटक को नक्सल

प्रभावित राज्यों की सूची से हटा दिया गया था। जुलाई 2011 में, नौ राज्यों में 83 जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या कम हो गई थी। दिसंबर 2011 में, राष्ट्रीय सरकार ने बताया कि राष्ट्रव्यापी नक्सलियों से संबंधित मौतों और चोटों की संख्या 2010 के स्तर से लगभग 50% कम हो गई थी।

2011 में, भारत सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में अविकसित क्षेत्र, सारंडा क्षेत्र, के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सारंडा एक्शन प्लान लॉन्च किया। ग्रामीण मंत्रालय के सदस्य, झारखंड सरकार और विश्व बैंक की टीमों भी इस योजना में हिस्सा लेती हैं और क्षेत्र में काम करती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास करना है और साथ ही इन क्षेत्रों में माओवादी संघर्ष को खत्म करना है।

आलोचना:

इस दृष्टिकोण की भी निम्न कारणों से आंशिक सफलता की कहानी है:

1. कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार ने इस दृष्टिकोण की आंशिक सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारें क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए बड़ी धनराशि प्रदान करती हैं, विद्रोहियों के लिए आकर्षक आत्मसमर्पण नीति शुरू करती हैं और इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए अन्य पहल करती हैं, लेकिन स्थानीय ढांचे में निहित भ्रष्टाचार पूरे प्रयासों को बेकार कर देता है।
2. इसके पीछे एक और कारण है 'प्रभावी पुलिस-व्यवस्था की अनुपस्थिति'। हालांकि, विद्रोहियों को हिंसा की घटना में लिप्त होते हैं और वे राज्य मशीनरी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ किसी भी संदिग्ध मुखबिरो पर हमला करते हैं। राज्य को उनसे निपटने के लिए हिंसा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, राज्य विद्रोहियों को नियंत्रित करना चाहता है और जैसा कि अक्सर होता भी है; विद्रोहियों और निर्दोष ग्रामीणों या वनवासियों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता है, इसलिए संपार्श्विक नुकसान (कोलेट्रल डेमेज) बड़ी संख्या में हो जाता है। इस प्रकार, विद्रोहियों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा नीति अक्सर स्थानीय लोगों के खिलाफ चली जाती है और यह दिल और दिमाग जीतने के पूरे प्रयासों को विफल कर देता है।